

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अधिशाली निदेशक,
आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र (DMMC)
सचिवालय परिसर, देहरादून।

आपदा प्रबन्धन अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक 02 नवम्बर 2016

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्राकृतिक आपदा के कारण अहेतुक सहायता आदि मदों में धनाबंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड राज्य में माह जून, 2013 में घटित भीषण प्राकृतिक आपदा के परिणाम स्वरूप व्यापक हानि के दृष्टिगत उत्तराखण्ड राज्य के साथ ही विभिन्न प्रदेशों के लापता/मृतक व्यक्तियों को प्रधान मंत्री राहत कोष से रू० 2.00 लाख तथा एस०डी०आर०एफ० की मद से रू० 1.50 लाख दिये जाने का प्राविधान किया गया है।

शासनादेश सं०-546/XVIII-(2)F/14-12(03)/2014 दिनांक 31 मार्च, 2014 के द्वारा रू० 4107.00 लाख तथा शासनादेश सं०-818/XVIII-(2)/15-18(13)/2013 दिनांक 23 मार्च, 2015 के द्वारा रू० 1605.00 लाख अर्थात् कुल रू० 5712.00 लाख की स्वीकृति प्राकृतिक आपदा में लापता/व्यक्तियों के Next Of Kin को तत्समय जारी किये गये मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर एन०डी०आर०एफ० मद में कुल देय राहत राशि प्रति व्यक्ति रू० 1.50 लाख की दर से स्वीकृत की गई थी।

माह जून, 2013 में घटित प्राकृतिक आपदा में वर्तमान तक उत्तराखण्ड राज्य सहित विभिन्न राज्यों के कुल 3880 लापता/मृत व्यक्तियों को मा० प्रधान मंत्री राहत कोष से रू० 2.00 लाख तथा एन०डी०आर०एफ० का अंश रू० 1.50 लाख अर्थात् कुल रू० 3.50 लाख प्रति व्यक्ति की दर से रू० 135.80 करोड़ की धनराशि वितरीत की जा चुकी है, जिसके सापेक्ष एन०डी०आर०एफ० का कुल अंश रुपये 58.20 करोड़ भी सम्मिलित है, लापता/मृतक व्यक्तियों के विधिक वारीसानों को भुगतान तात्कालिकता को दृष्टिगत रखते हुए (रू० 5820 लाख-5712 लाख) अर्थात् रुपये 108.00 लाख का भुगतान भी अन्य कोष से किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि वर्तमान में भी विभिन्न राज्यों के 297 लापता/मृत व्यक्तियों के प्रकरण विचाराधीन हैं, जिन पर अन्य राज्यों के पंजीकरण अभिहित अधिकारी द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण पत्र एवं शासन स्तर पर नामित नोडल अधिकारी, संयुक्त सचिव, विकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन की संस्तुति/मांग के आधार पर आपदा प्रबन्धन विभाग के द्वारा भुगतान की कार्यवाही की जाती है, प्रकरण के अन्तिम निस्तारण के उपरान्त ही लेखों का अन्तिम मिलान किया जाना संभव होगा।

3- अतः उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अन्य राज्यों के लापता/मृत व्यक्तियों को एन०डी०आर०एफ० मद के अन्तर्गत वर्तमान तक निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर देय राहत राशि की अवशेष धनराशि रू० 108.00 लाख तथा अवशेष 297 लापता/मृत व्यक्तियों हेतु एन०डी०आर०एफ० की कुल धनराशि रू० 445.50 लाख अंश के सापेक्ष रुपये 92.00 लाख अर्थात् (कुल रू० 108.00 + 92.00 लाख) अर्थात् कुल रू० 200.00 लाख (रू० दो करोड़ मात्र) इस शर्त के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि उक्त धनराशि को तत्काल आहरित करते हुए भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय परिसर में प्रधानमंत्री राहत कोष के नाम से संचालित खाता सं०-33370504295 में जमा कराये जाने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराया जायेगा।

(2)

- 4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिस मद हेतु उक्त धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
- 5- उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के लेखों का रख-रखाव एवं शासन द्वारा समय-2 पर निर्गत वित्तीय नियमों/दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 6- स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.3.2017 तक उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।
- 7- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्यय अनुदान सं०-6 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2245-प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत-05 राज्य आपदा मोचन निधि (90 प्रतिशत केन्द्र पोषित)-आयोजनेत्तर-800 अन्य व्यय-00-13-आपदा राहत निधि से व्यय-42-अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।
- 8- यह आदेश वित्त अनुभाग-5 के अ.शा. पत्र सं०-145 NP/XXVII(5)/2016 दिनांक 26 अक्टूबर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)

सचिव

संख्या-१९३ /XVIII-(2)/2016-18(13)/2013, तददिनांक ।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, देहरादून।
2. सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
5. निदेशक, कोषगार, पेंशन एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड।
- ✓ 6. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. बजट अधिकारी, बजट राजकोषकीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय उत्तराखण्ड।
8. वित्त अनुभाग-5 उत्तराखण्ड शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बड़ोनी)

उप सचिव